

Regarding need to separate insurance activities in banks in order to ensure growth in deposits

श्री अरुण गोविल (मेरठ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह चिंता का विषय है कि बैंकों में डिपॉजिट बढ़ने की रफ्तार क्यों कम हो रही है। देश की आम जनता बैंकों को कुबेर का खजाना मानती रही है। ऐसे में जब नवभारत टाइम्स जैसा प्रतिष्ठित अखबार 20 अगस्त, 2024 को यह खबर छापता है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्ति कांत दास ने बैंकों में घटते डिपॉजिट पर हाल ही में चिंता जतायी। जब केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भी इस बात पर चिंता जताते हुए बैंकों से डिपॉजिट बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा तो देश की जनता हैरानी में डूब गई। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश के बैंकों की मदद के लिए एक लाख करोड़ रुपये के बॉण्ड जारी कर रहा है, ताकि फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपकी मांग क्या है?

श्री अरुण गोविल (मेरठ) : महोदय, मेरी यही डिमांड है कि बैंकों का जो डिपॉजिट है, उसके बारे में अब बैंकों में यह कहा जा रहा है कि आप इश्योरेंस ले लीजिए। बैंकों का डिपॉजिट इश्योरेंस की वजह से कम होते चला जा रहा है। इश्योरेंस वालों को बैंक्स बहुत सारी सुविधाएं दे रही हैं। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि बैंकों से बैंक का काम कराया जाए और इश्योरेंस कंपनियों से इश्योरेंस का काम कराया जाए। बैंकों पर इश्योरेंस का लोड बढ़ने के कारण बैंक डिपॉजिट बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है। इससे भविष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं को फाइनेंस करने में समस्या आ सकती है। इसलिए बैंकों को बीमा के काम से अविलंब मुक्त करा दिया जाए। धन्यवाद।